

भारत की कृषि सब्सिडी पर थाईलैंड की चिंता

प्रलिस के लिये:

[वशिव व्यापार संगठन](#), [सार्वजनिक वितरण प्रणाली](#), शांतिखंड, [न्यूनतम समर्थन मूल्य](#), केर्न्स गुरुप

मेन्स के लिये:

भारत की कृषि सब्सिडी पर थाईलैंड की चिंता, WTO सुधार, सब्सिडी बॉक्स के मुद्दे, WTO सुधारों पर भारत के सुझाव।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [वशिव व्यापार संगठन](#) में थाईलैंड के राजदूत ने भारत पर सरकारी सब्सिडी द्वारा वित्तपोषित अनुचित रूप से न्यूनतम मूल्य पर चावल निर्यात करने का आरोप लगाया।

- थाईलैंड के अनुसार भारत की [सार्वजनिक वितरण प्रणाली](#), जिसके तहत सरकार उत्पादकों से आवश्यक खाद्य पदार्थ खरीदती है और उन्हें कम दरों पर जनता को बेचती है, वह लोगों के लिये नहीं बल्कि निर्यात बाजार पर "अधिग्रहण" करने के लिये है।

भारत की कृषि सब्सिडी को लेकर थाईलैंड की चिंताएँ क्या हैं?

- व्यापार विकृति और वैश्विक खाद्य मूल्य पर प्रभाव:**
 - थाईलैंड भारत के [सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम](#) को अत्यधिक सब्सिडी वाला मानता है, जो वैश्विक खाद्य मूल्यों को विकृत करता है।
 - व्यापार विकृति एक ऐसी स्थिति है** जहाँ कीमतें और उत्पादन उस स्तर से अधिक या कम होते हैं जो आमतौर पर प्रतस्पर्धी बाजार में मौजूद होते हैं।
 - सब्सिडी वाले कृषि उत्पादन से अधिक उत्पादन हो सकता है और कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे थाईलैंड जैसे गैर-सब्सिडी वाले प्रतस्पर्धियों के लिये वैश्विक बाजार में प्रतस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा।
- WTO नियमों का उल्लंघन:**
 - भारत द्वारा चावल सब्सिडी के लिये **न्यूनतम सीमा का उल्लंघन** WTO नियमों का उल्लंघन है। यह उल्लंघन न केवल प्रतस्पर्धी परदृश्य को प्रभावित करता है बल्कि कृषि पर WTO के समझौते द्वारा स्थापित नषिपक्ष व्यापार के सिद्धांतों को भी कमजोर करता है।
 - WTO के नियम के अनुसार **दिया जाने वाला समर्थन न्यूनतम 10% की सीमा के भीतर** होना चाहिये। भारत ने WTO को सूचित किया कि सत्र 2019-20 में उसके चावल उत्पादन का मूल्य 46.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि **उसने अनुमत 10% के मुकाबले 6.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 13.7% की सब्सिडी दी**।
- कृषि व्यापार उदारीकरण की इच्छा:**
 - केर्न्स समूह** के हिससे के रूप में, थाईलैंड कृषि व्यापार उदारीकरण का समर्थन करता है।
 - समूह वैश्विक कृषि बाजारों को विकृत करने वाली व्यापार बाधाओं और सब्सिडी को कम करना चाहता है, जिसमें [न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना](#) के दायरे को खत्म करने या कम करने के लिये भारत के वरिद्ध पैरवी करना भी शामिल है।

WTO AGREEMENT ON AGRICULTURE (AoA)

A WTO treaty negotiated during the Uruguay Round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT); formally ratified in 1994 at Marrakesh, Morocco; Came into effect in 1995

FEATURES

- Market access (Promote market access for agricultural products by reducing trade barriers)
- Domestic support (Subsidy Boxes are included in this)
- Export subsidies (Reduce the use of export subsidies, which can distort trade)

SUBSIDY BOXES

Amber Box Subsidies:

- Can distort international trade by making a country's products cheaper in comparison to those of other countries
- Examples: Subsidies for inputs such as fertilisers, seeds, electricity, irrigation, and Minimum Support Price (MSP)
- Amber box is used for all domestic support measures that are deemed to distort production and trade
 - As a result, the signatories are required to commit to reducing domestic supports that fall into the amber box
- Members who do not make these commitments must keep their amber box support within 5–10% of their value of production. (*De Minimis Clause*)
 - 10% for developing countries
 - 5% for developed countries
- India's MSP program remains under scrutiny, as it exceeds 10% ceiling

Blue box Subsidies:

- "Amber box with conditions" – designed to reduce distortion
- Any support that would normally be in the amber box is placed in the blue box if it requires farmers to limit production
 - These subsidies aim to limit production by imposing production quotas or requiring farmers to set aside part of their land
- At present there are no limits on spending on blue box subsidies

Green Box Subsidies:

- Domestic support measures that don't cause trade distortion or at most cause minimal distortion
- These subsidies are government funded without any price support to crops
 - Also include environmental protection and regional development programmes
- Allowed without limits (except in certain circumstances)



//

विकास बॉक्स:

- WTO के तहत कृषि समझौते का अनुच्छेद 6.2, विकासशील देशों को घरेलू सहायता प्रदान करने में अतिरिक्त लचीलेपन की अनुमति देता है।
- इनमें नविश सब्सिडी शामिल है जो आमतौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कृषि के लिये उपलब्ध है, कृषि इनपुट सब्सिडी आमतौर पर विकासशील देश के सदस्यों में कम आय अथवा संसाधन गरीब उत्पादकों के लिये उपलब्ध है और साथ ही यह बढ़ते अवैध नशीले पदार्थों रोकने में फसल वविधीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु विकासशील देश के उत्पादकों के घरेलू समर्थन को भी शामिल करता है।

WTO सब्सिडी मानदंड से संबंधित भारत की चर्चाएँ क्या हैं?

- **वकिसति देशों के साथ तुलना:**
 - भारत अमेरिका एवं **यूरोपीय संघ** जैसे वकिसति देशों की तुलना में कसिानों को दी जाने वाली सब्सडि के बीच भारी अंतर पर जोर देता है।
 - भारत प्रत्येक कसिान को बहुत कम 300 डॉलर की सब्सडि देता है, लेकनि अमेरिका एवं यूरोपीय संघ प्रत्येक कसिान 40,000 अमेरिकी डॉलर तक की सब्सडि की पेशकश कर सकते हैं।
 - यह तुलना वकिसति एवं वकिसशील देशों के बीच कसिानों को प्रदान की जाने वाली सहायता में असमानता को उजागर करती है।
- **डी-मनिमिसि लमिटि का उल्लंघन:**
 - भारत स्वीकार करता है कि उसने सब्सडि के लिये **10% न्यूनतम सीमा का उल्लंघन** किया, जिससे वर्ष 2013 में स्थापित "शांति खंड" शुरू हो गया।
 - वकिसशील देशों को सब्सडि स्तरों के उल्लंघन की चुनौती से बचाने के लिये बाली समझौते के तहत वर्ष 2013 में अंतरिम शांति खंड लागू किया गया था।
 - हालांकि भारत ने WTO में सब्सडि की गणना के तरीके पर प्रश्न उठाते हुए कहा है कि इसकी गणना वर्ष 1986-88 की एक नश्चिती और पुरानी कीमत पर की जाती है, जो सब्सडि को अधिक आकलन करती है।
 - भारत, कृषि पर WTO वार्ता में इसे बदलने की मांग कर रहा है।
- **स्थायी समाधान की आवश्यकता:**
 - भारत, वकिसशील देशों के एक समूह के साथ खाद्यान्न के लिये सार्वजनिक भंडारण के संबंध में स्थायी समाधान की वकालत करता है।
 - इस समाधान का उद्देश्य वकिसशील देशों को सब्सडि स्तरों के उल्लंघन की चुनौतियों का सामना किये बिना कृषि सहायता हेतु अधिक लचीलापन प्रदान करना है।

केरन्स ग्रुप एवं G-33 ग्रुप क्या हैं?

- **केरन्स ग्रुप:**
 - स्थापना: वर्ष 1986 में केरन्स, ऑस्ट्रेलिया में
 - सदस्य: 19 कृषि निर्यातक देश, जिनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, पाकिस्तान एवं न्यूजीलैंड आदि शामिल हैं।
 - भारत, केरन्स समूह का सदस्य नहीं है।
 - मुद्रा: कृषि व्यापार के उदारीकरण के समर्थक है जिसका अर्थ कविे आमतौर पर टैरिफि, सब्सडि एवं अन्य व्यापार बाधाओं को कम करने का समर्थन करते हैं और साथ ही सीमाओं के पार कृषि उत्पादों के मुक्त प्रवाह में बाधा भी डालते हैं। उनका मानना है कि इससे दक्षता एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर सभी देशों को लाभ होगा।
- **G-33 ग्रुप:**
 - गठन: इसका गठन वर्ष 2003 में आयोजित कैनकन मंत्रसित्रीय सम्मेलन से पूर्व किया गया।
 - सदस्य: मूल रूप से इसमें 33 वकिसशील देश शामिल थे कति वर्तमान में इसमें जिनमें भारत, चीन और क्यूबा सहित लगभग 48 देश शामिल हैं।
 - रुख: यह समूह कृषि व्यापार वार्ता में वकिसशील देशों के लिये विशिष प्रावधान का समर्थन करता है।
 - उनका तर्क है कि वकिसशील देशों को अपने घरेलू कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चिती करने के लिये अधिक लचीलेपन की आवश्यकता है, भले ही इसके लिये कुछ व्यापार बाधाओं को बनाए रखना पड़े।
 - उन्होंने संबद्ध देशों की आजीविका और ग्रामीण विकास पर पूर्ण व्यापार उदारीकरण के संभावित नकारात्मक प्रभावों के संबंध में भी चिंता जताई।

वशि्व व्यापार संगठन (WTO) का शांति समझौता क्या है?

- एक अंतरिम उपाय के रूप में **वशि्व व्यापार संगठन** के सदस्यों ने दसिंबर 2013 में 'पीस क्लॉज़/शांति समझौता' नामक एक तंत्र पर सहमत जिताई और स्थायी समाधान के लिये बातचीत करने का संकल्प लिया।
- शांति उपबंध के तहत वशि्व व्यापार संगठन के सदस्यों ने **वशि्व व्यापार संगठन के वविाद समाधान फोरम** में वकिसशील राष्ट्रों द्वारा निर्धारित सीमा में कसिी भी उल्लंघन को चुनौती देने से बचने पर सहमत वियकृत की।
- यह उपबंध तब तक बना रहेगा जब तक कि खाद्य भंडारण के मुद्दे का स्थायी समाधान नहीं हो जाता।

आगे की राह

- भारत को सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर स्थायी समाधान की अपनी मांगों पर जोर देने के लिये WTO के साथ वार्ता जारी रखनी चाहिये। इसमें प्रमुख हतिधारकों के साथ द्विपक्षीय चर्चा और WTO की बैठकों तथा वार्ताओं में सक्रिय भागीदारी शामिल हो सकती है।
- भारत अन्य वकिसशील देशों के साथ गठबंधन को सुदृढ़ कर सकता है जो कृषि सब्सडि और समर्थन तंत्र के संबंध में समान चिंता तथा मांग को साझा करते हैं। **G-33 ग्रुप** जैसे गठबंधन स्थापित कर भारत अपने मुद्दों का प्रासार कर सकता है और WTO वार्ता के अंतर्गत अन्य देशों की सहायता से समूह में सौदेकारी के विकल्प का चयन कर सकता है।
- भारत को नीति भिंचों, अनुसंधान संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के माध्यम से कृषि सब्सडि तथा समर्थन तंत्र पर अपने रुख को बढ़ावा देना चाहिये। इसमें खाद्य सुरक्षा के महत्त्व और वकिसशील देशों के लिये कृषि सहायता प्रदान करने में अनुकूलनीय होने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना शामिल है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमि कया? (2018)

- (a) अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- (b) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
- (c) व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन
- (d) विश्व व्यापार संगठन

उत्तर: (d)

प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लॉज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015)

- (a) खाद्य और कृषि संगठन
- (b) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का रूपरेखा सम्मेलन
- (c) विश्व व्यापार संगठन
- (d) संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम

उत्तर: (c)

प्रश्न 3. नमिनलखिति में से किसके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मलिते हैं? (2016)

- (a) WTO मामला
- (b) SAARC मामला
- (c) UNFCCC मामला
- (d) FTA पर भारत-यूरोपीय संघ वार्ता

उत्तर: (a)

प्रश्न 4. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2017)

1. भारत ने WTO के व्यापार सुकर बनाने के करार (TFA) का अनुसमर्थन कया है ।
2. TFA, WTO के बाली मंत्रसितरीय पैकेज 2013 का एक भाग है ।
3. TFA जनवरी 2016 में प्रवृत्त हुआ ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 5. 'व्यापार-संबंधति नविश उपायों' (TRIMS) के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

1. वदिशी नविशकों दवारा कयि जाने वाले आयात पर 'परमिणात्मक नरिबधन' प्रतबिध नषिदिध होते हैं ।
2. ये वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधति नविश उपायों पर लागू होते हैं ।
3. ये वदिशी नविश के नयिमन से संबंधति ही हैं ।

नीचे दयि गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2
- (c) केवल 1 और 3
- (d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न 1. WTO एक महत्त्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए नरिणय देशों को गहराई से प्रभावति करते हैं। WTO का क्या अधदिश (मैडेट) है और उसके नरिणय कसि प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर वचिर-वमिरश के पछिले चकर पर भारत के दृढ-मत का समालोचनापूर्वकवशिलेषण कीजयि। (2014)

प्रश्न 2. "WTO के अधकि व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नतकिरना है। परंतु (संधा) वार्ताओं की दोहा परधिभृतांमुखी प्रतीत होती है जसिका कारण वकिसति और वकिसशील देशों के बीच मतभेद है।" भारतीय परपिरेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजयि। (2016)

प्रश्न 3. यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परदृश्य में वशिव व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़दिा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्तर हैं, वशिष रूप से भारत के हति को ध्यान में रखते हुए? (2018)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/thailand-s-concern-over-india-s-agriculture-subsidy>

